http://amritkalashtimes.com

अमृत कलश टाइम्स

वर्ष : 18
अंक : 86

प्रयागराज गुरुवार 12 दिसम्बर 2024

पृष्ठः- 4, मूल्यः- एक रूपया

पीएम ने सुब्रमण्यम भारती को किया याद

● उनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थीः मोदी

नई दिल्ली,(एजेंसी)। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में शब्दों को केवल अभिव्यक्ति ही नहीं माना गया है। हम उस संस्कृति का हिस्सा हैं, जो 'शब्द ब्रह्म' की बात करती है, शब्द के असीम सामर्थ्य की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण कृतियों के संग्रह का विमोचन किया। इन कृतियों को 23–खंडों के सेट में सीनी विश्वनाथन ने संकलित और संपादित किया है। इसमें भारती के लेखन के संस्करणों, स्पष्टीकरणों, दस्तावेजों, पृष्ठभूमि की जानकारी और दार्शनिक प्रस्तुति का विवरण शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा, श्आज देश महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जन्मजयंती मना रहा है। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।श श्आज तमिलनाडु के गौरव के लिए बहुत बड़ा अवसरश उन्होंने आगे कहा कि आज भारत की संस्कृति और साहित्य के लिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों के लिए और तमिलनाडु के गौरव के लिए बहुत बड़ा अवसर है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती के कार्यों का, उनकी रचनाओं का प्रकाशन एक बहुत बड़ा सेवायज्ञ और बहुत बड़ी साधना है। और आज उसकी पूर्णाहुति हो रही है। हमारे देश में शब्दों को केवल अभिव्यक्ति ही नहीं माना गया है। हम उस संस्कृति का हिस्सा हैं, जो 'शब्द ब्रह्म' की बात करती है, शब्द के असीम सामर्थ्य की बात करती है। हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित पीएम मोदी ने कहा कि सुब्रमण्यम भारती ऐसे महान मनीषी थे, जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काम करते थे। उनका विजन बहुत व्यापक था। उन्होंने हर उस दिशा में काम किया, जिसकी जरूरत उस कालखंड में देश को थी। भारतियार केवल तमिलनाडु और तमिल भाषा की ही धरोहर नहीं है, वो एक ऐसे विचारक थे जिनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थी। उन्होंने कहा, श्सुब्रह्मण्य भारती जैसा व्यक्तित्व सदियों में कभी एक बार मिलता है। उनका चिंतन, उनकी मेधा, उनका बहु–आयामी व्यक्तित्व... ये आज भी हर किसी को हैरान करता है।

सीएम योगी ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएंः बोले....

गरीबों की जमीन कब्जामुक्त कराएं

● जनता दर्शनः सीएम योगी का निर्देश–गरीबों की जमीन कब्जा मुक्त कराएं, दबंगों को सिखाएं सबक, भू–माफियाओं पर करें कड़ी कार्रवाई

गोरखपुर,(एजेंसी)। सीएम योगी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक–एक करके, इत्मीनान से सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गरीबों की जमीन कब्जामुक्त कराएं और अवैध कब्जा करने वाले दबंगों को करारा कानूनी सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का संकल्प है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जमीन कब्जा करने के मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक–एक करके, इत्मीनान से सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सबको न्याय मिलेगा और सबकी पीड़ा दूर की जाएगी। जनता दर्शन में दूसरे जिलों के भी लोग आए थे। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं ने भूमाफिया और दबंगों द्वारा जमीन कब्जा करने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमाफिया को करारा सबक सिखाया जाएगा। उनके रहते कोई भी किसी कमजोर या गरीब को उजाड़ नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया।

आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत शर्तो में ढील

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए जमानत की शर्तों में बुधवार को ढील दे दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की जमानत के मामले में अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को हर सोमवार और गुरुवार को संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की शर्त जरूरी नहीं है हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें नियमित रूप से निचली अदालत में उपस्थित होना चाहिए। श्री सिसोदिया ने

हर सोमवार और गुरुवार को संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की जमानत की शर्तों में ढील के लिए शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी। उच्चतम न्यायालय ने गत नौ अगस्त को श्री सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)– दोनों मामलों में जमानत देकर उन्हें बड़ी राहत दी थी। अदालत ने यह देखते हुए जमानत दी थी कि मुकदमे की सुनवाई में देरी और श्री सिसोदिया के लंबे समय तक जेल में रहने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर असर पड़ रहा है। शीर्ष अदालत ने जमानत की शर्तों में श्री सिसोदिया को प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने जमानत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई, 2024 के आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को उपमुख्यमंत्री रहते हुए 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।

लोकसभा स्पीकर से राहुल की मुलाकात

● बीजेपी के आरोपों को आधारहीन बताया, अपने खिलाफ हुई टिप्पणियां हटाने की मांग की

नई दिल्ली,(एजेंसी)। राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा में 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा चाहती है और वह सुनिश्चित करेंगे कि सदन ठीक ढंग से चले, जबकि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। राहुल ने कहा, ष्मैंने अभी स्पीकर के साथ बैठक की और उन्हें बताया कि हमारी पार्टी चाहती है कि मेरे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाया जाए। स्पीकर ने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे। वह (भाजपा के लोग) हर तरह के आधारहीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमने फैसला किया है कि हम सदन को ठीक ढंग से चलने देना चाहते हैं।ष उन्होंने कहा, ष्वह चाहे कुछ भी भड़काऊ बात कहें, हम उन्हें कहने देंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे और सदन चलने देंगे। हम चाहते हैं किसी तरह सदन की कार्यवाही चलती रहे। हम चाहते हैं कि सदन में बहस और चर्चाएं हों। हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हो।ष राहुल ने कहा कि भाजपा सांसद मेरे खिलाफ जिस मुद्दे पर चाहें, उस पर बोलें, लेकिन संविधान के मुद्दे पर बहस होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अदाणी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। हम इस मुद्दे को अंत के लिए नहीं छोड़ना चाहते। इस बीच जब राहुल गांधी से भाजपा के उन आरोपों पर सवाल पूछा गया, जिनमें जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के जुड़ाव की बात कही गई तो इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ष्वह आरोप लगाना जारी रखेंगे। उन्हें मेरे खिलाफ आरोप लगाने दीजिए। हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चलती रहे।ष गौरव गोगोई ने भी अपमानजनक टिप्पणी रिकॉर्ड से हटाने की मांग की इससे पहले, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने लोकसभा अध्यक्ष से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर मुख्य विपक्षी दल की शिकायत पर गौर करने और उन्हें रिकॉर्ड से हटाने की अपील की थी।

अगले पांच साल में भारत वैश्विक ऑटो उद्योग का करेगा नेतृत्वः गडकरी

नई दिल्ली,(एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास जताया है कि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग अगले पांच वर्षों में वैश्विक स्तर पर नंबर एक स्थान पर पहुंच जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने मंत्रालय का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रेखांकित किया कि दो वर्षों में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को 9 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग हुआ बड़ा मंगलवार को अमेजन संभव शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग की उल्लेखनीय बढ़ोतरी का जिक्र किया। जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उनके पदभार

संभालने के बाद से यह 7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है। तीसरे नंबर से पहले पर आना है उन्होंने कहा, ष्पहला स्थान अमेरिका का है – 78 लाख करोड़ रुपये का, दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग चीन में है – 47 लाख करोड़ रुपये का, और अब भारत 22 लाख करोड़ रुपये का है। मुझे विश्वास है कि 5 साल के भीतर हम भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं।ष भारत में लॉजिस्टिक्स लागत मंत्री ने कहा कि भारत में प्रतिष्ठित वैश्विक ऑटोमोबाइल ब्रांडों की मौजूदगी देश की क्षमता का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने आगे कहा कि उनके मंत्रालय का लक्ष्य 2 वर्षों के भीतर भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को एक अंक तक कम करना है। उन्होंने कहा, श्भारत में लॉजिस्टिक लागत 16 प्रतिशत है और चीन में यह 8 प्रतिशत है, अमेरिका और यूरोपीय देशों में यह 12 प्रतिशत है।

कितनी बदली दिल्ली की सियासत?

● सीएम से डिप्टी सीएम तक जेल गए, मंत्रियों ने पद के साथ पार्टी भी छोड़ी

नई दिल्ली,(एजेंसी)।दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। उधर सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आप 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो सूची जारी कर चुकी है जिसमें कुल 31 नाम हैं। आइये जानते हैं पिछले पांच साल में दिल्ली की सियासत में क्या–क्या बदला..? दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी और पार्टी ने अब तक कुल 31 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आप ने अपनी दोनों सूचियों में हाल ही में आए दूसरे दलों से आए नेताओं को भी मौका दिया है। उधर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली न्याय यात्रा निकाली। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकालने का एलान किया है। पांच साल में दिल्ली कई सियासी उठापटक का गवाह रही है। दो चेहरों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जहां एक ओर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाई गई तो दूसरी ओर कुछ मंत्रियों ने दल बदल लिया। अब वो विपक्षी दलों के साथ हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के केंद्र में कथित शराब घोटाला भी रहा। इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसे हैं। जेल से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी कैबिनेट में मंत्री रहीं आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। आइये जानते हैं कि राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे रहे थे? चुनाव के बाद राज्य की राजनीति कितनी बदली? किन मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी? सरकार का रूप कितना बदला? अभी कैसी स्थिति है? पार्टियों ने चुनाव की तैयारी कैसे की है? पहले जानते हैं पिछली बार विधानसभा चुनाव कब हुए थे? चुनाव आयोग ने 7 जनवरी 2020 को पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। कार्यक्रम के तहत 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी 2020 को मतदान हुआ था। इसमें कुल 62.59: फीसदी मतदान दर्ज किया गया था। नतीजे 11 फरवरी 2020 को घोषित किए गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे थे? फरवरी 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने प्रचंड जीत दर्ज की थी।

पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 62 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। आप को सबसे ज्यादा 53.57: वोट मिले थे। वहीं, भाजपा के आठ विधायक चुने गए थे और इसका वोट प्रतिशत 40.57: रहा।

रेल संचालन को और सरल बनाने वाला 'रेल संशोधन विधेयक' लोकसभा में पारित

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। लोकसभा ने रेलवे के संचालन को ज्यादा सरल और सुविधाजनक बनाने तथा स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को ज्यादा शक्ति देने के वास्ते दो पुराने कानूनों को जोड़कर बनाया गया 'रेल संशोधन विधेयक –2024' बुधवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सदस्यों ने कई अच्छे सुझाव दिए हैं। विधेयक की आवश्यकता संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि विधेयक को सरल बनाने की जरूरत थी और इसमें 1905 तथा 1989 के संशोधन को मिलाकर कानून को सरल बनाया गया है। रेलवे का बहुत विकेंद्रीकरण हुआ है और उसका देश को बड़ा लाभ हुआ है क्योंकि

अधिकारियों को लोगों की जरूरत के अनुसार काम करने का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले दस साल के दौरान रेलवे में स्वच्छता के स्तर पर बहुत बदलाव आया है। इन दौरान करीब तीन लाख दस हजार नये टॉयलेट बनाए गये हैं और स्वदेशी तकनीकी से वंदेभारत रेल शुरु की गई और इसकी वजह से इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। छोटी दूरी दो से ढाई सौ किलोमीटर की दूरी पर नमो भारत रेल चल रही हैं। रेल लाइनों का बड़े स्तर पर विद्युतिकरण हुआ है। इसका फर्क यह है कि 60 साल में 21 हजार लाइनों का विद्युतिकरण हुआ था, लेकिन इन दस साल में 44 हजार किलोमीटर का विद्युतिकरण हुआ है। रेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में खूब निवेश हुआ है, लेकिन रेलवे में कम हुआ है और इधर रिकार्ड कायम हुए हैं। मोदी सरकार ने 31 हजार नये ट्रैक बनाए हैं और एक साल में पांच हजार से अधिक रेलवे के नये ट्रैक बने हैं। रेलवे को लेकर निजीकरण की किसी भी तरह की गलत अवधारणा नहीं बनाने की उन्होंने विपक्षी दलों से आग्रह किया और कहा कि इस तरह की अवधारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। और स्वीकार करना चाहिए कि देश ने रेलवे के क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। सरकार ने सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए रेल के जनरल कोच बढाए गये हैं।

अकेले लड़ेंगे चुनावः केजरीवाल

● गठबंधन का सवाल ही पैदी नहीं होताः राघव चड्ढा

नई दिल्ली,(एजेंसी)। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबरों पर अरविंद केजरीवाल ने विराम लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात अंतिम चरण में है। गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों को भी शामिल करने की बात सामने आई। कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 15 सीटें और अन्य इंडिया गठबंधन सदस्यों को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी।

दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी ।।च्रू केजरीवाल एएनआई की ओर से सूत्रों के हवाले से किए गए दावे पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए खंडन किया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर एनआई के पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा, श्आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन को कोई संभावना नहीं है।श कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहींरू संजय सिंह आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, श्पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। आप अकेले ही चुनाव लड़ेगी।श गठबंधन का सवाल ही पैदी नहीं होतारू राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, श्मैं स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आप अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी।

किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदी नहीं होता।श दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अब तक दो सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची में पार्टी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का एलान किया। वहीं, दूसरी सूची में सोमवार को 20 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उम्मीद है कि फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जनवरी में चुनाव आयोग चुनावों की तारीख का एलान भी सकता है।

सम्पादकीय

किसानों को सड़क पर लाती सरकार

कृषि उत्पादों पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सी–2 प्लस 50 प्रतिशत के फार्मूले के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग को लेकर दिल्ली प्रवेश कर रहे किसानों को हरियाणा स्थित शंभू बॉर्डर पर रोकने में पुलिस को चाहे सफलता मिल गयी हो लेकिन किसान नेता अगले कदम पर विचार–विमर्श कर रहे हैं। उधर सड्डुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खाली कराये जाने की एक जनहित याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसी आशय की एक अजी ंपहले से ही उसके समक्ष विचाराधीन है इसलिये नयी याचिका का औचित्य नहीं है। तत्काल सुनवाई की आवश्यकता से भी उसने इंकार कर दिया। इस सिलसिले में शीर्ष न्यायालय ने पहले ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जनता का मौलिक अधिकार बतलाया था और प्रशासन को किसानों के साथ बातचीत कर समस्या का हल निकालने का सुझाव दिया था। बहरहाल, किसान नये सिरे से इस आंदोलन को आगे बढ़ायें। सरकार को चाहिये कि इस जायज मांग को तत्काल स्वीकार कर उन्हें संतुष्ट करे। अपने ऐलान के मुताबिक रविवार को जब हजारों की संख्या में किसानों ने अपनी ट्रैक्टर–ट्रॉलियों के साथ बॉर्डर पार करने की कोशिश की तो वहां मौजूद बड़ी संख्या में पुलिस ने उन्हें रोक लेने में कामयाबी पाई। उसके पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जिससे करीब आधा दर्जन किसान घायल हो गये। एक की स्थिति बहुत गम्भीर बताई गई है जिसे चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में भर्ती कराया गया है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन सोमवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया। स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले चिकित्सकों के अनुसार उनकी सेहत लगातार खराब हो रही है। आंदोलनकारी किसानों के प्रति पहले की सी बेरुखी अपनाते हुए केन्द्र सरकार उनके साथ चालबाजियां कर रही है। शुक्रवार को आंदोलन के नेताओं से कहा गया कि वे बिना ट्रैक्टर–ट्रॉली के सरकार से मिलने आ सकते हैं परन्तु शनिवार को जब उन्होंने जाने की कोशिश की तो उन्हें यह कहकर रोका गया कि केवल 10 लोगों को ही जाने की मंजूरी है। रविवार को पुलिस और प्रशासन ने यह आरोप लगाकर उन्हें रोक दिया कि मिलने हेतु जाने वाले किसान अपना परिचय नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते शंभू बॉर्डर पर अप्रिय स्थिति बन गयी। हालांकि किसानों ने स्वयं ही अपने कदम वापस खींच लिये और स्वीकार किया कि पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया है। वे आपस में विचार कर अगला कदम तय करेंगे। केन्द्र सरकार के इस रवैये से साफ है कि वह पूर्ववत हठधर्मी बनी हुई है और वह किसानों के इस मुद्दे को लेकर कतई संजीदा नहीं है। उल्लेखनीय है कि 2020–21 में किसानों ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल 4 माह का आंदोलन किया था (9 अगस्त, 2020–11 दिसम्बर, 2021)। उस आंदोलन में 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे। उस समय तो पुलिस ने उन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिये बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थीं। उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड में उन पर पानी की बौछारें की गयीं, डंडे बरसाये गये, शरीर पर आंसू गैस के गोले फेंके गये, रबर बुलेट भी शरीर के ऊपरी हिस्सों में चलाई गयीं। इतना ही नहीं, सड़कों पर कीलें लगाई गयीं और पक्के किस्म के बैरिकेड तक लगा दिये गये थे। अभी इसी साल हुए लोकसभा चुनावों के पहले फरवरी में किसानों ने फिर से आंदोलन किया, तो सरकार व पुलिस ने अपनी जनविरोधी मानसिकता का एक और रूप दिखाते हुए हरियाणा व दिल्ली के बीच खाइयां तक खोद दी थीं। एक तरफ केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार खुद को किसान हितैषी बतलाती है, तो दूसरी ओर वह किसानों की मांगों को पूरा करना तो दूर, उनसे बात करने के लिये तक तैयार नहीं है। किसानों द्वारा जिस प्रकार से कृषि कानूनों को वापस लेने के लिये मोदी को मजबूर किया गया, उससे लगता है कि अब सरकार ने तय कर लिया है कि वह आंदोलनकारियों से कोई संवाद नहीं करेगी। किसानों के साथ होने वाला उसका बर्ताव तो कम से कम यही दर्शाता है। कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए हालांकि श्री मोदी ने कहा था कि, वे किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पर हैं और वे जब भी चाहें उनसे मिल सकते हैं।श उस बात को अब तीन वर्ष हो चुके हैं परन्तु पीएम हों या उनके कोई जिम्मेदार मंत्री, किसी के पास इतना वक्त नहीं हैय और न ही मंशा है कि वे किसानों को सामने बिठाकर बातचीत करें और किसानों को राहत दें। यह भी लोगों को अब तक याद है कि श्री मोदी ने दावा किया था कि 2022 तक वे किसानों की आय को दोगुना करेंगे। वह साल भी कब का गुजर चुका है। इन सबसे सरकार की मंशा साफ है कि वह किसानों से कोई बात करना नहीं चाहती तथा उसे इतना हताश व निराश कर देना चाहती है कि वे इस मांग को ही भूल जायें। अपने लोगों से हाईवे को खाली कराने की याचिकाएं डलवाना भाजपा का पुराना हथकण्डा है जो पहले भी किसान आंदोलन और शाहीन बाग आंदोलन के वक्त आजमाया जा चुका है। सिनेमा से राजनीति में आईं भाजपा की सासंद कंगना रनौत ने चुनाव जीतने के कुछ दिनों के बाद ही कह दिया था कि कृषि कानूनों को फिर से लागू किया जाना चाहिये।श हालांकि वह उनका अधिकृत बयान नहीं था और उन्हें इसके लिये माफी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन वह भाजपा की आम राय प्रतीत होती है। किसानों के साथ सरकार का सुलूक तो यही दर्शाता है।

किसानों की मांगों का ठोस हल निकलना चाहिए

जानकारों का कहना है कि किसानों की मांग और सरकारी सिस्टम के बीच कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिसकी वजह से हाल के दिनों में इसके सुलझने के आसार कम ही दिख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर–राजनीतिक) के मुताबिक किसानों की सबसे बड़ी मांग सभी फसलों को एमएसपी की गारंटी देने की है।

एमएसपी और कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का मुद्दा संसद में भी गूंज रहा है और सरकार उनकी मांगों का हल निकालने की बात कह रही है। राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहते हैं और इस पर काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री के बयान से इतर किसानों का मसला सुलझाना इतना भी आसान नजर नहीं आ रहा है। जानकारों का कहना है कि किसानों की मांग और सरकारी सिस्टम के बीच कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिसकी वजह से हाल के दिनों में इसके सुलझने के आसार कम ही दिख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर–राजनीतिक) के मुताबिक किसानों की सबसे बड़ी मांग सभी फसलों को एमएसपी की गारंटी देने की है। किसान संगठन चाहते हैं कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएस स्वामीनाथन की सिफारिश वाला फॉर्मूले हो। किसान संगठनों की दूसरी बड़ी मांग गन्ना और हल्दी को लेकर है। संगठन का कहना है कि गन्ना की खरीदी भी स्वामीनाथन की सिफारिश पर ही की जानी चाहिए। किसानों की एक अन्य मांग कृषि क्षेत्र को प्रदूषण से बाहर रखने की भी है। आंदोलन के अगुवा सरवन सिंह पंढेर के मुताबिक हमारी कुल 12 मांगें है, जिस पर पहले भी सरकार से बातचीत हो चुकी है। सरकार ने पहले इस पर ठोस एक्शन की बात कही थी, लेकिन अब सरकार सुन नहीं रही है। असल में किसानों की मांग के बीच विश्व व्यापार संगठन के पेच हैं। किसान सभी फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी चाहते हैं। अगर केंद्र लीगल गारंटी देती है तो सभी सभी फसलों की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही उसे करनी होगी, लेकिन इसमें एक पेच विश्व व्यापार संगठन का है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार से जुड़े वैश्विक नियमों को तय करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन है। भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है और उसके शर्तों पर हस्ताक्षर कर चुका है। डब्ल्यूटीओ ने अपनी शर्तों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी न देने की बात कहा है। विश्व व्यापार संगठन सिर्फ सब्सिडी देने की बात कहता है। यानी सरकार अगर इसे लागू करती है तो उसे पहले डब्ल्यूटीओ की सदस्यता छोड़नी होगी, जो कि आसान नहीं है। यही वजह है कि हाल के दिनों में किसान संगठनों ने डब्ल्यूटीओ के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। कृषि राज्य का मसला है– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में कृषि का जिक्र है। इसमें कृषि को राज्य का विषय बताया गया है। हालांकि, योजना लागू करने और अन्य अधिकार केंद्र के पास भी है। 2020 में संसद के मानसून सत्र में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सांसद फूलो देवी नेताम के एक सवाल के जवाब में भी कृषि को राज्य का मसला बताया था। यानी राज्य ही इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। अभी किसान अपनी मांगों को केंद्र से मनवाने पर अड़ी है। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र इस मसले पर बिल लेकर आए और संसद से पास कराए। विपक्ष भी इस मांग को उठा रही है, लेकिन केंद्र अगर ऐसा करती है तो यह संवैधानिक संकट के दायरे में आ जाएगा। अगर इसे कोर्ट में चौलेंज किया जाए तो नए सिरे से बहस छिड़ सकती है, जिससे केंद्र पर ही सवाल उठेगा। क्योंकि, अगर इसे राज्य स्वीकार कर लेती है तो भविष्य में पुलिस और अन्य राज्य के मसले में भी केंद्र दखल दे सकती है। वही मसला यह भी है कि लागत कैसे तय हो, यह भी सवाल– एक पेच फसलों की लागत को लेकर भी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि लागत किसान ही तय करें, तभी बात बन सकती है। किसान संगठनों का कहना है कि स्वामीनाथन के फॉर्मूले को वर्तमान की महंगाई के हिसाब से तय किया जाए. जब यह रिपोर्ट बनाई जा रही थी, तब मजदूरों को कम पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब मजदूरी सबसे ज्यादा बोझ हो गया है। किन फसलों पर मिले एमएसपी इस पर भी संशय है। सरकार उन फसलों पर ही एमएसपी देना चाह रही है, जो वर्तमान में डिमांड में है। इनमें दलहन और तिलहन की फसलें हैं। सरकार ने हालिया एमएसपी की लिस्ट में इन फसलों की दामों में बढ़ोतरी भी की है। उत्तर और दक्षिण भारत के अधिकांश किसान रबी में गेहूं और खरीफ धान उपजाने का काम करता है। किसानों को इसी का ज्ञान भी है। ऐसे में किसान क्या करें? किसान संगठन सभी फसलों पर संपूर्ण एमएसपी देने की मांग कर रहा है. किसानों के मुद्दे पर बीते दिनों राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाकि, ''कृषि मंत्री जी, एक–एक पल आपका भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपा कर मुझे बताएं कि क्या किसानों से वायदा किया गया था? वायदा क्यों नहीं निभाया गया? वायदा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। कालचक्र घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं!'' हालांकि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी पर कुछ नहीं कहा और इस संबंध में गठित समिति पर भी सवाल नहीं किया, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में किसानों को एक ताकतवर, सशक्त पैरोकार मिला है। शिवराज भी जून, 2024 में ही कृषि मंत्री बने हैं। जो भी वायदे किए गए होंगे, वे नरेंद्र तोमर और अर्जुन मुंडा के कृषि मंत्री काल के होंगे! बहरहाल भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का 17 फीसदी से अधिक का योगदान है और देश के कार्यबल में करीब 47 फीसदी कृषि और किसान का योगदान है। देश की करीब दो–तिहाई आबादी कृषि के भरोसे है, लेकिन आज भी किसान की औसत आय 16,928 रुपए माहवार है। किसान की आय से अधिक खर्च बढ़े हैं और प्रति किसान 91,000 रुपए से अधिक का कर्ज है। यदि एक बार फिर राजधानी दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में किसान लामबंद होकर आंदोलन छेड़ते हैं, तो चौतरफा जन–व्यवस्था अराजक हो जाएगी। जब पिछला किसान आंदोलन समाप्त कराया गया था, तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया था। एक समिति गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को सौंपी गई थी। उन्हें तीन कथित काले कृषि कानूनों का प्रारूपकार माना जाता रहा है।

बगलबच्चा पूंजीवाद से माई–बाप पूंजीवाद तक

क्या क्रोनी कैपीटलिज्म यानी बगलबच्चा पूंजीवाद की संज्ञा पुरानी नहीं पड़ गयी है? क्या विशेष रूप से भारत में हालात अब बगलबच्चा पूंजीवाद से आगे नहीं निकल गए हैं। आम तौर पर देश के राजनीतिक मंच पर और खासतौर पर संसद में पिछले कुछ समय से जो कुछ हो रहा है, उससे तो ऐसा ही लगता है। जहां तक संसद का सवाल है, अब यह करीब–करीब साफ ही हो गया है कि पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र मोदी सरकार द्वारा अडानी के बचाव की भेंट चढ़ने जा रहा है। अमेरिका में अडानी की कंपनियों के खिलाफ प्रतिभूति बाजार नियामक तथा एफबीआई की जांच के बाद, भारत में अडानी ग्रुप की सौर बिजली की खरीद का रास्ता साफ करने के लिए, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के अधिकारियों को 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दिए जाने के प्रकरण के अमेरिका से संबंधित मामले में आरोप तय कर मुकद्दमे की कार्रवाई शुरू किए जाने की खबर आने के बाद, संसद में विपक्ष द्वारा जोरदार तरीके से इस मुद्दे का उठाया जाना स्वाभाविक था। लेकिन, जब सरकार के और उसके आधीन नियामक एजेंसियों तथा विभिन्न जांच एजेंसियों के श्अडानी जांच से परे हैश की मुद्रा अपनाने से आगे बढ़कर, मोदी राज ने सदनाध्यक्षों के जरिए यह सुनिश्चित किया कि अडानी का नाम संसद में श्उल्लेख से भी परेश रहना चाहिए, तभी यह तय हो गया था कि संसद के शीतकालीन सत्र में कम से कम सामान्य तरीके से काम–काज नहीं होने जा रहा है। और वही हुआ भी। शीतकालीन सत्र का आधे से ज्यादा हिस्सा, अडानी के मुद्दे पर बहस की विपक्ष की मांग और सत्तापक्ष की किसी भी कीमत पर ऐसी कोई चर्चा नहीं होने देने की जिद के बीच रस्साकशी में ही निकल गया। बहरहाल, इसी दौरान अपने बगलबच्चा पूंजीपति के बचाव के लिए, मोदी राज के अड़े रहने के सिवा और भी काफी कुछ हो रहा था, जो कम दिलचस्प नहीं था। बगलबच्चे की तरह, सत्ता का संरक्षण पा–पाकर ताकतवर हुए इजारेदार पूंजीपति के हिमायतियों का दायरा सिर्फ सत्ता में बैठी ताकतों तक ही सीमित नहीं होता है। उसकी थैलियों के मुंह सत्तापक्ष से बाहर भी संरक्षण हासिल कर लेते हैं या लिए रहते हैं। इसलिए, संसद में जब सत्तापक्ष पर अडानी प्रकरण पर बहस कराने का दबाव एक हद से ज्यादा बढ़ा, विपक्ष की कतारों में इस बगलबच्चा पूंजीवाद के संरक्षत्व को सामने आने के लिए उत्प्रेरित करना शुरू कर दिया गया। विपक्ष की कतारों में इसकी आवाजें उठनी शुरू हो गयीं कि अडानी का मुद्दा कोई सबसे जरूरी मुद्दा नहीं है। पहले शरद पवार ने गौतम अडानी से अपनी दोस्ती की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के जरिए, उसके लिए समर्थन को सामान्य बनाने की कोशिश की। उसके बाद, ममता बैनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया कि संसद में उसकी प्राथमिकताएं कांग्रेस से भिन्न हैं। अडानी प्रकरण उसकी प्राथमिकता पर नहीं है। अंततरू समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ही प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का राग अलापना शुरू कर दिया। इस तरह, लोकसभा चुनावों के बाद से जो नहीं हुआ था, हो गया और अडानी के ही मुद्दे पर विपक्ष की कतारों में दरारें दिखाई देने लगीं। लेकिन, अडानी के बचाव के लिए इतना भी काफी नहीं था। इसकी एक सीधी सी वजह यह थी कि राज्यों के लिए सौर ऊर्जा की आपूर्ति के सौदे में भ्रष्टाचार का तत्व इस कदर आंखों में गड़ने वाला था कि विपक्ष की कतारों में क्रोनी पूंजीपति के सरपरस्तों की मौजूदगी के बावजूद और विपक्ष में इस मामले पर मतभेद उभर आने के बावजूद, इस मामले का दबना आसान नहीं था। इस पृष्ठभूमि में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ इस मुद्दे पर डटे रहने का नतीजा यह था कि विपक्ष में थोड़ी–बहुत किचकिच के बावजूद, आम तौर पर विपक्ष इस मुद्दे पर कमोबेश एकजुट ही नजर आता था और उसकी आवाज को अनसुना कर के संसद में तथा आम तौर पर राजनीतिक मंच पर सामान्य स्थिति बहाल नहीं की जा सकती थी। अब क्रोनी पूंजीपति के बचाव की उसी दुहरी कार्यनीति का अगला और ज्यादा आक्रामक दांव शुरू किया गया। विपक्ष के स्तर पर, खासतौर पर हरियाणा और अब महाराष्ट्र की विपक्ष की चुनावी हार के बहाने से, कांग्रेस पर सीधे हमला बोल दिया गया कि वह विपक्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने में असमर्थ साबित हो रही है। अब ममता बैनर्जी ने सीधे–सीधे विपक्षी कतारबंदी का नेतृत्व संभालने के लिए अपने तैयार होने का ऐलान कर दिया। चुनाव के धक्के से और अन्यान्य कारणों से भी, जिनमें बड़े धनपतियों से चुनावी चंदे हासिल करने में अपनी हिस्सेदारी भी शामिल है, कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी ममता बैनर्जी की दावेदारी को उचित मानने की बातें करनी शुरू कर दीं। असली मकसद यही था कि लड़ाई के बीच में, इस लड़ाई में आगे–आगे चल रही कांग्रेस के, प्रायरू समूचे विपक्ष की ओर से बोलने के दावे को कमजोर किया जाए। दूसरी ओर, सत्ताधारी भाजपा ने खुद सीधे कांग्रेस पर यह कहते हुए, सारे विधि–निषेधों को ताक पर रखते अंधाधुंध हमला छेड़ दिया कि अडानी पर हमला, अडानी पर हमला नहीं है, वास्तव में नरेंद्र मोदी के राज पर हमला है, भारत के विकास पर हमला है, आदि। फ्रांसीसी समाचार पोर्टल, मीडियाअपार्ट की एक कथित रूप से खोजी रिपोर्ट के बहाने से और उसके निष्कर्षों पर, अपने ही दावे थोपते हुए।

, स्वतंत्र मीडिया संस्थान आर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने से आगे बढ़कर, उसकी फंडिंग के बहाने उसे जॉर्ज सोरोस से लेकर, अमरीकी विदेश विभाग तक, श्भारत विरोधियों का हथियारश तो करार दिया ही गया, कांग्रेस को इस भारत–विरोधी षड्यंत्र का कर्ताधर्ता बना दिया गया। और यह सब किसलिए? गौतम अडानी को बचाने के लिए! इसके बहाने से सत्ताधारी पार्टी ने संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई ठप्प करने की जिम्मेदारी खुद ही संभाल ली। इस सब के दूरगामी राजनीतिक नतीजों का तो अभी अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन, कांग्रेस के खिलाफ अपने हमले को सत्ताधारी पार्टी ने जिस स्तर पर पहुंचा दिया है, वहां से शेष शीतकालीन सत्र का इसी गतिरोध में निकल जाना तय लगता है। इसके साथ ही यह गौरतलब है कि मोदी राज किस तरह अडानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है? विपक्ष और उसमें भी खासतौर पर कांग्रेस पर उसका हमला करना तो फिर भी समझ में आ सकता है, लेकिन जिस तरह से इस हमले में अमरीकी शासन तथा राज्य को भी घसीट लिया गया है, वह उसकी बदहवासी को ही दिखाता है। बेशक, इसके लिए विपक्ष को ही नहीं, अमेरिका को भी गाली देकर, वे भारत में अपनी कतारों को यह समझाने में मदद मिलने की उम्मीद कर सकते हैं कि क्यों उनका अडानी को बचाना देश के लिए जरूरी है, वगैरह। लेकिन, उनकी अपनी कतारों से भी यह विडंबना पूरी तरह से छुपी तो नहीं रह सकती है कि श्भारत के विरुद्ध विदेशी षड्यंत्रश का यह बहाना एक ऐसी सरकार बना रही है, जो सबसे ज्यादा अमेरिका के इशारों पर चलने वाली सरकार रही है। श्विदेशी हाथश के इंदिरा गांधी के नारे का इस्तेमाल करने की कोशिश अब एक ऐसी सरकार कर रही है, जो अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव तक में अपनी भूमिका तलाश करती आई है। इस सबसे तो ऐसा ही लगता है कि बात क्रोनी कैपीटलिस्ट यानी बगलबच्चा पूंजीपति पर कृपा बनाए रखने, उसे मुसीबतों से बचाने से बहुत आगे निकल चुकी है। अब हम माई–बाप पूंजीवाद या ओनर कैपीटलिज्म के कारनामे देख रहे हैं। क्रोनी यानी बगलबच्चे को एक हद तक ही बचाया जा सकता है। बात उस हद से आगे चली जाए, तो उसे डूबने के लिए छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन, माई–बाप पूंजीपति तो माई–बाप पूंजीपति है, उसे बचाने के लिए तो किसी भी हद तक जाना होगा, कुछ भी करना होगा। अब अडानी और मोदी निजाम का ठीक ऐसा ही रिश्ता है। मोदी निजाम को अडानी को बचाने के लिए खुद डूबना भी पड़ा तो, खुद डूबकर भी बचाने की कोशिश करेगा। यह दूसरी बात है कि इसमें पूरे शक की गुंजाइश है कि अडानी, मोदी निजाम के लिए ऐसी ही कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा।

बाबरी मस्जिद विध्वंस के 32 साल बाद निशाने पर कई अन्य स्थल

अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किये जाने के 32 साल, तथा 9 नवंबर, 2019 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच–न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिये गये अयोध्या फैसले के लगभग पांच साल बाद जिसमें राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया गया,अनेक अन्य स्थलों को निशाना बनाया गया है। अयोध्या फैसले के तहत राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2024 को कर भी दिया, परन्तु फैसले को आधे–अधूरे ढंग से लागू किया गया, जिसके कारण कई अन्य मस्जिदें और दरगाह नये लक्ष्य बन गये, जिससे देश भर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव और वैमनस्य पैदा हो रहा है, जो अयोध्या के फैसले से बढ़ी उम्मीदों के विपरीत है। 2024 के भाजपा के घोषणापत्र में मंदिर के निर्माण को श्लोगों का पांच–सदियों पुराना सपना बताया गया था, जो अब सच हो गया है। इसके बाद तो सांप्रदायिक तनाव पैदा होना और भड़कना बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा के वैचारिक मूल स्रोत आरएसएस और हजारों सिर वाले सांप्रदायिकतावादी अनियंत्रित हो गये, और काशी और मथुरा में मस्जिद और दरगाह को निशाना बनाया, जो उनकी पुरानी मांग थी। सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय अन्य मस्जिदों और दरगाहों को निशाना नहीं बनाने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच समझौता हुआ था। अयोध्या फैसले ने भी पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को बरकरार रखा जिसमें किसी और पूजा स्थल के चरित्र को नहीं बदलने का प्रावधान है,और जिसे धर्मनिरपेक्षता की पूर्ति घोषित किया, जो भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। कई लक्ष्यों में, बहुप्रकाशित लक्ष्य हैं, टीले वाली मस्जिद, लखनऊ, उत्तर प्रदेशय कुव्वत–उल–इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, दिल्लीय ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी, उत्तर प्रदेशय कमाल मौला मस्जिद, भोजशाला परिसर, मध्य प्रदेशय शम्सी शाही मस्जिद, बदायूं, उत्तर प्रदेशय अटाला मस्जिद, जौनपुर, उत्तर प्रदेशय शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा, उत्तर प्रदेशय जामा मस्जिद, संभल, उत्तर प्रदेशय फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की जामा मस्जिद और दरगाहय और अजमेर शरीफ दरगाह, राजस्थान। अन्य कम प्रकाशित लक्ष्य भी हैं। अयोध्या फैसले के पांच न्यायाधीश थे– जस्टिस रंजन गोगोई, एसए बोबडे, डॉ डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर। कई पूर्व न्यायाधीशों ने जहां पर मस्जिद को ध्वस्त किया गया उस जगह पर मंदिर के निर्माण की अनुमति देने वाले इस फैसले की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नरीमन ने कहा कि इस मामले में –श्न्याय का एक बड़ा उपहासश यह हुआ कि धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया गया। फिर भी, अयोध्या फैसले में पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखना फैसले के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जहां तक सांप्रदायिक तनाव और वैमनस्य पर पूर्ण विराम लगाने का सवाल है। हालांकि, पीठ के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने 2022 के एस निर्णय में पूजा स्थल अधिनियम तथा भारत के संविधान के मूल उद्देश्य की अनदेखी करके एक गंभीर गलती की, जिनमें से किसी में भी सांप्रदायिक तनाव और वैमनस्य की परिकल्पना नहीं की गयी थी। काशी ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है, भले ही इसका उपयोग बदला न जा सके। इसने मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ मामलों की बाढ़ ला दी, जो अंततरू सांप्रदायिक अशांति का कारण बन रहे हैं। अयोध्या फैसले में भारत की संसद के इरादों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में दिये गये स्पष्टीकरण को उद्धृत किया गया हैरू श्हम इस विधेयक को प्रेम, शांति और सद्भाव की हमारी गौरवशाली परंपराओं को प्रदान करने और विकसित करने के उपाय के रूप में देखते हैं। ये परंपराएं एक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता अनादि काल से हमारी महान सभ्यता की विशेषता रही है।श अयोध्या फैसले में पूजा स्थल अधिनियम का उद्देश्य श्नये विवाद पैदा नहीं करना और पुराने विवादों को नहीं उठाना है, जिन्हें लोग लंबे समय से भूल चुके हैंश। फैसले में कहा गया है कि श्1991 में संसद द्वारा पारित पूजा स्थल अधिनियम संविधान के मौलिक मूल्यों की रक्षा करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

यह मानवीय गरिमा और बंधुत्व पर जोर देती है। सभी धार्मिक विश्वासों की समानता के लिए सहिष्णुता, सम्मान और स्वीकृति बंधुत्व का एक मौलिक सिद्धांत है। पूजा स्थल अधिनियम भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए एक अपरिवर्तनीय दायित्व लागू करता है। इसलिए यह कानून भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा के लिए बनाया गया एक विधायी साधन है, जो संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। गैर–प्रतिगमन मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों की एक आधारभूत विशेषता है, जिसका एक मुख्य घटक धर्मनिरपेक्षता है। इस प्रकार पूजा स्थल अधिनियम एक विधायी हस्तक्षेप है जो गैर–प्रतिगमन को हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक आवश्यक विशेषता के रूप में संरक्षित करता है। अयोध्या फैसले ने धर्मनिरपेक्षता को एक संवैधानिक मूल्य के रूप में बरकरार रखा, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच के फैसले का हवाला देते हुए।

लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार, गिरोह के छह आरोपी पकड़े गए, फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य सामान बरामद

वाराणसी। लुटेरी दुल्हन ये शब्द थोड़ा फिल्मी जरूर लग रहा होगा लेकिन वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसी महिला को पकड़ा है जो शादी तो करती है लेकिन वो शादी पैसे के नाम पर धोखा देने के लिए होती है और इसके पीछे पूरा गिरोह काम कर रहा होता है। पुलिस ने महिला समेत गिरोह के छह आरोपी गिरफ्तार किया है और इनके पास से फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। फर्जी दुल्हन बनकर 1.17 लाख की धोखाधड़ी के मामले में लंका पुलिस ने गिरोह की लुटेरी दुल्हन समेत छह आरोपियों को सामनेघाट से मंगलवार को गिरफ्तार किया। सभी के पास से फर्जी आधार कार्ड और मोबाइल बरामद हुए। राजस्थान के रहने वाले पीड़ित ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। लंका इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया

कि गिरफ्तार आरोपियों में राजस्थान के सिकरा निमका थाने क्षेत्र के पुरानबास निवासी सुमेर सिंह, टोक मालपुरा निवासी प्रसन कुमार, कौशांबी के मंझनपुर स्थित भ्रारस्वा निवासी अनिल और बिहार निवासी तीन महिलाएं शामिल हैं। रविवार को शादी हुई थी और सोमवार को पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया था। सभी को जेल भेज दिया गया है। पीड़ित घनश्याम के अनुसार सुमेर सिंह ने कहा था कि मेरी साली संगीता है। यदि तुम्हें पसंद होगी तो शादी करवा दूंगा। सुमेर की बात पर विश्वास कर अपने छोटे भाई महाबीर राम के साथ वाराणसी आया। सुमेर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में संगीता से मिलवाया। मौके पर लड़की के फूफा अनिल, जीजा प्रसन कुमार, मां, बुआ मौजूद थीं। दुल्हन पसंद होने बाद लंका स्थित नगवा में एक मकान में ले जाकर शादी करवाई। शादी की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन की विदाई कराकर मंडुवाडीह पहुंचे तो लड़की बहाना बनाकर अपने कथित भाई के साथ बाइक पर बैठकर भाग निकली। धीरे–धीरे अन्य सभी लोग फरार हो गए। बाद में पता चला कि इन लोगों ने फर्जीवाड़ा कर एक लाख सत्रह हजार रुपये ले लिए हैं। यह लोग लड़की के रिश्तेदार नहीं थे बल्कि गैंग के सदस्य थे।

रकम वसूली का बड़ा नेटवर्क, राजस्थान से फंसाकर युवकों लाते थे

लंका इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि सुमेर सिंह राजस्थान का रहने वाला है। अविवाहित लोगों को फंसाकर लेकर शादी कराने के लिए वाराणसी लाता है। लड़की दिखाने से लेकर शादी कराने तक का कार्यक्रम गिरोह के सदस्य करते हैं। लड़की के परिजन (मां, बहन, बुआ, जीजा, बहनोई) सब काल्पनिक होते हैं। यह लोग लड़के की तरफ से मिले रुपये आपस में बांट लेते हैं। स्टेशन पर ट्रेन आने के पूर्व ही लड़की बहाना बनाकर फरार हो जाती है। इनका संगठित गिरोह है, जो पैसे के लिए धोखाधड़ी करता है। आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाया जा रहा है।

मधुबन में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता में बिना जूतों के दौड़ीं बेटियां

मधुबन। तहसील के कुंडा शरीफपुर स्थित तरुण इंटर कॉलेज के मैदान पर मंगलवार को दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय बेसिक शिक्षा परिषदीय खेलकूद प्रतियोगिता में छात्राएं नंगे पांव बिना जूतों के दौड़ीं। नंगे पांव दौड़ रही छात्राओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुख्य अतिथि बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। 600 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में धनराज यूपीएस फतेहपुर मंडाव पहले, प्रिंस सिद्धा अहिलासपुर को दूसरा और लधुवाई के अमन तीसरे स्थान पर रहे। 600 मीटर बालिका वर्ग में कुंडा शरीफपुर की रंजना प्रथम, सिद्धा अहिलासपुर की परी दूसरे और सलोनी पांती तीसरे स्थान पर रहीं। 400 मीटर की दौड़ में बालिका वर्ग में अंशिका यादव हैवतपुर को पहला, मुढाडार की अंकिता दूसरा और सोनी अजोरपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में आरजू पदारथपुर पहले, हरिकेश पांती दूसरे, प्रिंस लालनपुर तीसरे नंबर पर रहे। 100 मीटर बालिका वर्ग में वंदना साहनी यूपीएस मधुबन प्रथम, आशु कुंडा द्वितीय और मधुबन की राधा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 100 मीटर बालक वर्ग में प्रिंस सिद्धा प्रथम, शिवम फतेहपुर द्वितीय, सुंदरम लधुवा तृतीय रही। 50 मीटर प्राथमिक बालिका वर्ग आंचल चांदपुर रामपुर प्रथम, सुनैना गंगऊपुर द्वितीय, शिवानी कुंडा तीसरे स्थान पर रही। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह ने कहा कि खेलकूद से बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। स्वास्थ्य मस्तिष्क का विकास होता है। बीडीओ श्याम सुंदर पटेल ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा नेता राहुल दीक्षित, सभासद राजकुमार, शिक्षक सत्य प्रकाश, नीतेश,अरुण हिंद, विवेक राव, संजय सिंह, मनमोहन पांडेय, दिलीप सिंह, अजय पटेल, भूपेश सिंह आदि मौजूद रहे।

मऊ की शिवांगी ने बनारस की सपना को दी पटखनी

रानीपुर। गोविंद दशमी पर मंगलवार को ब्लॉक के धर्मसीपुर गांव स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में कुश्ती प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में पहलवानों ने दावं पेंच का प्रयोग कर एक दूसरे को पटखनी दी। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने पहलवानों का हाथ मिलाकर कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पहली कुश्ती महाराजपुर के सर्वेंद्र और मुहम्मदाबाद के पिंटू के बीच हुई। सर्वेंद्र ने दांव के आगे पिंटू चित हो गए। मुहम्मदाबाद के मंगला और बकरी के अभिषेक यादव की कुश्ती बराबरी पर छूटी। भलया के सुंदरम और बकरी के अभय यादव की कुश्ती हुई। भलया के सुंदरम विजयी रहे। सरवा के शत्रुघ्न और धवरियासाथ के रेहान के बीच कुश्ती हुई। कुश्ती में शत्रुघ्न विजयी रहे। बनारस की सपना और मऊ की शिवांगी के बीच कुश्ती हुई। मऊ की शिवांगी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बनारस की सपना को पटखनी देकर जीत दर्ज की। आजमगढ़ के रमाशंकर और बनारस के नेहरू के बीच हुई कुश्ती बराबरी पर रही। बनारस के धर्मेंद्र और बलिया के अर्जुन के बीच हुई कुश्ती बराबरी पर रही। भलया के रामनयन और बलिया के धनंजय के बीच कुश्ती बराबरी पर रही। बनारस के अरविंद और सरवा के अभिमन्यु की कुश्ती बराबरी पर रही। आखिरी कुश्ती बनारस के राजेश और भलया के मनोहर के बीच हुई कुश्ती बराबरी पर रही। इस मौके पर पूर्व प्रमुख अरुण कुमार सिंह, डॉ. उमेश सरोज, क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र कुमार, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मप्रकाश यादव, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि पंकज यादव, लालबहादुर यादव, सूर्यभान यादव, मनोज कुमार, हरिवंश यादव, गिरजाशंकर यादव, रामकुमार भारती आदि शामिल रहे।

एसआई सहित दो पुलिसकर्मियों को एसपी ने किया सस्पेंड

वाराणसी। एसपी आदित्य लांग्हे ने अवैध धन उगाही कर मिट्टी का खनन कराने के आरोपी बलुआ थाने के एसआई सहित दो पुलिसकर्मियों को मंगलवार की शाम सस्पेंड कर दिया। बताया कि दोनों के खिलाफ गंभीर अरोप लगे हैं। इन्हें निलंबित कर विभागीय जांच कराई जा रही है। एसपी आदित्य लांग्हे लगातार लापरवाही और गलत कार्यों में लिप्त पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले महीने चोरी और लूट के मामले में लापरवाही पर चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। वहीं मंगलवार को बलुआ थाने के एसआई पारसानाथ यादव और मुख्य आरक्षी ऋषिकांत द्विवेदी को क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन कराने और उससे अवैध वसूली कराने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। एसपी आदित्य लांग्हे ने देर शाम जारी विज्ञप्ति में बताया कि थाना बलुआ पर नियुक्त उपनिरीक्षक पारसनाथ यादव और मुख्य आरक्षी ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कार्य कराए जाने और उससे अवैध धन की उगाही किए जाने का तथ्य संज्ञान में आया है। इसे संज्ञान में लेते हुए दोनों को पदेन दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, शिथिलता व अनुशासनहीनता बरतने संबंधित गंभीर आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच कराई जा रही है।

तालाब पार करने की लगाई शर्त और डूबकर हार गया जिंदगी

वाराणसी। थाना क्षेत्र के कुआं गांव में आकाश उर्फ काजू चौहान (18) दोस्तों से शर्त लगाने में अपनी जिंदगी ही हार गया। युवक की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। तीन दोस्तों में तालाब को तैरकर पार करने की 500 रुपये की शर्त रखी गई थी। काजू पहले कूदा और तालाब पार भी कर गया। लौटते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। थाना क्षेत्र के कुआं गांव के रहने वाले तीन युवक सोमवार की शाम तालाब किनारे बैठकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान तीनों दोस्तों के बीच तालाब पार करने को लेकर 500 रुपये की शर्त लग गई। इसके बाद आकाश चौहान ऊर्फ काजू तालाब में कूद गया और तालाब पार कर गया। इसके बाद लौटते समय वह बीच तालाब में डूबने लगा। यह देखकर उसके दोस्त तालाब में कूद गए और उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आकाश डूब चुका था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से सुबह ही आकाश को ढूंढने में लग गई लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल सका। इससे नाराज ग्रामीणों ने लेवा–इलिया मार्ग जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे सीओ चकिया राजीव कुमार सिशोदिया व थानाध्यक्ष मिर्जा रिजवान बेग ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और जाम छुड़वाया। दिन में लगभग 11 बजे गोताखोरों ने आकाश का शव तालाब से ढूंढ निकाला। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। परिवार वाले रो–रोकर बेहाल हैं। इस घटना से पूरे गांव में मातम छाया रहा।

पूर्वांचल के इस जिले की स्ट्रॉबेरी- ड्रैगन फ्रूट को मिलेगी नई पहचान, किसानों को मिलेंगे 126 करोड़ पौधे

वाराणसी। बनारस के औषधीय पौधों, फूलों के साथ मिर्जापुर के स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट को भी नई पहचान मिलेगी। पूर्वांचल के अन्य जिलों के फसलों को भी विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए किसानों को दो सालों में 126 करोड़ रोगमुक्त पौधे उपलब्ध कराएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत पूर्वांचल की बागवानी और फसलों को भी चुना गया है। बनारस के औषधीय पौधों, फूलों के साथ मिर्जापुर के स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट को भी विकसित किया जाएगा। वहीं, चंदौली में सब्जी के विस्तार की तैयारी है। ऐसे ही अन्य जिलों की फसलों का भी चयन हुआ है। इनको देश–प्रदेश में पहचान दिलाने की तैयारी है। किसानों को रोगमुक्त पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में सब्जियों से लेकर फलों की खेती होती है। उद्यान विभाग इसे बढ़ाने की तैयारी में है। हर जिले की अलग–अलग फसलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। बनारस दौरे में प्रदेश उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेशभर की बागवानी फसलों को चुना गया है। योजना के तहत पूर्वांचल के कई जिलों की फसलों का विकास होगा। बनारस में फूलों की खेती को बढ़ाया जाएगा। इससे पूरे देश के साथ विदेशों में भी निर्यात हो सकेगा। वनारस अभी अपनी क्षमता का 10 फीसदी उत्पादन कर पाता है। किसानों को मदद मिले तो उत्पादन बढ़ सकता है। मिर्जापुर में स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, चंदौली में सब्जी की खेती भी बढ़ेगी। राज्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 73 जिलों में दो–दो हाईटेक नर्सरियां बनाई जा रही है। रोगमुक्त पौधे उगाकर किसानों को कम दामों में दिए जाएंगे। वहीं, कुछ शहरों के एयरपोर्ट के पास इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क बनेंगे। बनारस में भी तीन नर्सरियां बन रही हैं। साल में 126 करोड़ रोगमुक्त पौधे देने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग ने 2026 तक किसानों को सब्जियों, फूलों आदि के 126 करोड़ रोगमुक्त पौधे देने का लक्ष्य रखा है। अभी किसानों को 16.74 करोड़ पौधे मिलेंगे। हाईटेक नर्सरियों के शुरू हो जाने से सामान्य किसानों को भी उन्नत किस्म के बीज और पौधे आसानी से मिल जाएंगे। किसान एक रुपये और बीज देकर पौधा तैयार करा सकेंगे। बीज के बिना पौधा चाहिए तो दो रुपये देने होंगे।

संगमरमर की दीवार पर अंकित हैं गीता के 700 लोक

वाराणसी। भगवान श्रीकृष्ण के श्रीमुख से निकली गीता की वाणी काशी की दीवारों पर भी अंकित है। चौखंभा स्थित वल्लभ गीता श्रीकृष्ण भवन (बेटी जी मंदिर) में गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक लिखे गए हैं। सफेद संगमरमर पर इन श्लोकों को 70 साल पहले अंकित किया गया है। यहां श्रद्धालुओं को गीता ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ती। वे सस्वर श्लोकों का पाठ करते हैं।

ऑपरेशन थियेटर में सर्जरी खत्म होते ही डॉक्टर की बिगड़ी तबियत, चंद मिनटों में तोड़ा दम

वाराणसी। वाराणसी में त्रिवेणी ट्रॉमा सेंटर के ऑपरेशन थियेटर में अचानक एक डॉक्टर की तबीयत बिगड़ी। जहां उनको प्राथमिक उपचार मिला, लेकिन उनकी मौत हो गई। अर्दली बाजार स्थित त्रिवेणी ट्रॉमा सेंटर के ऑपरेशन थियेटर (ओटी) में मंगलवार की शाम डॉक्टर अभिषेक राय की तबीयत बिगड़ गई। प्राथमिक उपचार मिला, लेकिन उनकी मौत हो गई। मौत किस वजह से हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा। डॉक्टर के करीबियों के मुताबिक, कार्डियक अरेस्ट से मौत की आशंका है। वैसे डॉक्टर राय पिछले तीन दिन से तेज बुखार, सांस फूलने की समस्या से ग्रसित थे। डॉ. अभिषेक ही ट्रॉमा सेंटर के संचालक थे। डॉ. अभिषेक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की वाराणसी इकाई के सदस्य होने के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी थे। अर्दली बाजार स्थित ट्रॉमा सेंटर में मंगलवार की शाम जैसे ही मौत की सूचना मिली, वैसे ही हर कोई हतप्रभ रह गया। डॉक्टर अभिषेक को जानने वाले लोगों के अनुसार, आठ दिसंबर को आईएमए की नई कार्यकारिणी गठित हुई थी। डॉ. अभिषेक भी मतदान करने आए थे। उस समय भी उन्होंने बुखार, छाती में दर्द के साथ ही सांस लेने में दिक्कत बताई थी। कहा था कि अपना उपचार करवा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, डॉ. अभिषेक मंगलवार को ट्रॉमा सेंटर में एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन खत्म ही हुआ था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहां मौजूद उनके सहयोगियों ने उन्हें पास में बिठाया। डॉक्टर ने जरूरी दवाइयां भी लीं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आईएमए के पूर्व पदाधिकारी बोले– अच्छा साथी खो दिया आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अभिषेक राय की मौत पर आईएमए के पूर्व पदाधिकारियों और सदस्यों ने दुख जताया। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरविंद सिंह, डॉ. संजय राय ने कहा कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही मन व्यथित है। हमने होनहार चिकित्सक और बेहतरीन साथी खो दिया। आईएमए के पूर्व सचिव डॉ. आरएन सिंह के साथ ही डॉ. कर्मराज सिंह, डॉ. अतुल सिंह आदि ने भी डॉ. अभिषेक की मौत पर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ जिला अस्पताल के सीनियर फिजीशियन डॉ. पीके सिंह ने भी उन्हें याद किया। देर रात सपा नेताओं के साथ ही शहर के डॉक्टरों ने उनके घर पर शोक संवेदनाएं जताईं। चिकित्सकों ने बताया कि वह बेहद ही मिलनसार थे। कार्यक्रमों में वह हमेशा बढ़–चढ़कर भाग लेते थे।

रोज 10 मशीनों पर 30 मरीजों की होती है डायलिसिस, इंतजार में 185 मरीज

मऊ। जिला अस्पताल में पहुंचने वाले किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को डायलिसिस की सुविधा समय से जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रही है। डायलिसिस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। डायलिसिस सेंटर पर क्षमता से छह गुना अधिक 183 वेटिंग चल रही है। जबकि रोज 28 से 30 मरीजों की तीन शिफ्ट में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक डायलिसिस हो रही है। जिला अस्पताल में मरीजों के डायलिसिस के लिए चार सितंबर 2021 में दीपचंद डायलिसिस सेंटर की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की गई है। उस समय छह मशीनें लगाई थीं। मई 2023 में चार नई मशीन लगाई गई, इससे डायलिसिस सेंटर और अधिक मरीजों का डायलिसिस का लाभ मिलने लगा। यहां पर जनपद के साथ पड़ोस के गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ और बलिया से भी मरीज आकर डायलिसिस करा रहे हैं। इस महीने में 183 मरीज डायलिसिस के लिए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का प्रतिक्षा कर रहे हैं। डायलिसिस सेंटर के मैनेजर वशिष्ट कुमार ने बताया कि सितंबर में 163 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अक्तूबर में इनकी संख्या 178 पर पहुंच गई। नवंबर में प्रतीक्षा सूची 180 पर पहुंच गई है। नवंबर माह में 780 मरीजों की डायलिसिस हुई थी। वहीं दिसंबर माह में अब तक 240 मरीजों की डायलिसिस हो चुकी है, तो 185 मरीज वेटिंग चल रहीं है। बेड सीमित मात्रा में होने से मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यहां मात्र 10 बेड होने की वजह से मरीजों की लंबी कतार लगी है। रोजाना यहां पर 28 से 30 मरीजों की डायलिसिस की जाती है। अस्पताल प्रशासन ने दस और बेड बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। आने वाले दिनों में दस और बेड लगने से सेंटर में रोजाना 63 मरीजों की डायलिसिस होगी। जबकि हर माह यहां करीब 1800 मरीजों की डायलिसिस की जा सकेगी।

17 साल पुराने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चार दोषी, परिवीक्षा पर छोड़े गए

मऊ। विशेष जज एससीएसटी एक्ट हरेंद्र प्रसाद ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चार आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाया। सभी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए दो माह तक सदाचार बनाए रखने की हिदायत देते हुए रिहा कर दिया। क्रॉस केस मामले में नामजद चार आरोपियों में तीन को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। एक आरोपी की मौत हो जाने के चलते उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार गंगऊपुर गांव निवासी हरिश्चंद्र की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें गांव के ही बृजेश व मंजेश, भोला और संजय पांडेय को नामजद किया। वहीं दूसरे पक्ष से श्रीकृष्ण राजभर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें शिवधर, हरिश्चंद्र, मुराली उर्फ मुरारी और सुभाष को नामजद किया। दोनों पक्षों का आरोप था कि चुनाव की रंजिश को लेकर 28 मई 2007 को रात्रि में 8 बजे मारपीट हुई। जिसमें तलवार से हमला किया गया। इसमें एक पक्ष के हरिश्चंद्र, मुराली और वासुदेव को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने एक पक्ष से सात व दूसरे पक्ष से आठ गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से एक दूसरे के क्रॉस केस का हवाला देते हुए झूठा फंसाने का आरोप लगाया। विशेष जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन के बाद एक पक्ष के बृजेश, मंजेश, भोला और संजय पांडेय को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने, गाली और धमकी देने का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद सभी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए दो माह तक सदाचार बनाए रखने के हिदायत देते हुए रिहा कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के हरिश्चंद्र, मुराली उर्फ मुरारी व सुभाष को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। आरोपी शिवधर की मृत्यु हो जाने के चलते उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।

पीडीडीयू जंक्शन पर चार लावारिस बैग में मिले 75 कछुए

वाराणसी। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने मंगलवार को स्थानीय रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग में पड़े 75 कछुओं को बरामद किया। जीआरपी ने कछुओं को वन विभाग के हवाले कर दिया। माना जा रहा है कि कछुओं को ट्रेन से बंगाल ले जाया जा रहा था। तस्कर ट्रेन बदलने के लिए स्टेशन पर उतरे होंगे और जीआरपी के डर से इसे छोड़ कर भाग गए। ठंड की शुरुआत होते ही कछुओं की तस्करी तेज हो गई है। तस्कर देहरादून, बिजनौर सहित अन्य इलाकों से कछुओं को पकड़ कर इसकी तस्करी पश्चिम बंगाल में करते हैं। यहां कछुओं को चाव से खाया जाता है। यहीं नहीं कई शक्तिवर्धक दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। मंगलवार की सुबह सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम गश्त कर रही थी। इस बीच प्लेटफॉर्म संख्या एक और दो पर चार बैग लावारिस हाल में मिले।

वाराणसी के निर्माण विभाग ने गिराई साख, 33 परियोजनाएं एक साल पीछे

वाराणसी। वाराणसी निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में साख गिराई। यहां 33 परियोजनाएं एक साल पीछे चल रही हैं। ऐसे में रैंकिंग में जिले के निर्माण विभाग को 10 में से एक नंबर मिले हैं। अप्रैल से अक्तूबर तक जारी हुई मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में निर्माण विभाग ने जिले की साख गिराई है। वाराणसी की 66 रैंक आई है। विभाग को 10 में से सिर्फ एक नंबर मिला है। उन्हें ई–ग्रेड दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सूची में अंतिम पांच जिलों में वाराणसी शामिल है। इसका मुख्य कारण परियोजनाओं का काम समय से पूरा न होना है। इसके अलावा लोक शिकायत विभाग को निर्माण (सीएमआईएस) कार्यों से जुड़े मामले में भी ई–ग्रेड दी गई है। जारी डैशबोर्ड की रैंकिंग के मुताबिक वित्तीय वर्ष में पुलों की लक्षित संख्या दो है। लेकिन, पूरे किए गए पुलों की संख्या शून्य है। स्वीकृत लागत (19591.15) लाख में आवंटन हुआ है (774.73) लाख में और व्यय राशि शून्य रही। सेतुओं के भौतिक सत्यापन में वाराणसी 50 फीसदी नंबर मिले हैं और उसी हिसाब से रैंक 66 रही। इसी आधार पर ई ग्रेड जारी किया गया। 10 में नौ नंबर पाने वाले जिलों को ए प्लस, 8 नंबर पाने वालों को ए, 6 नंबर पाने वाले को बी, 4 नंबर पाने वालों को सी और 2 नंबर पाने वाले को डी और इससे कम नंबर पाने वाले को ई–ग्रेड दी जाती है। इसके अलावा निर्माण विभाग को नई सड़कों के निर्माण में सी ग्रेड दिया गया है। जिले को ओवरऑल 10 में 8.13 नंबर मिले हैं, इसके साथ ही जिले को 56वीं रैंक दी गई है। विकास कार्यों से जुड़ी रैंक 11वीं है और राजस्व से संबंधित रैंक 66वीं हैं। बी और डी ग्रेड में रहन वाले विभाग ग्राम विकास विभाग को डे एनआरएलएम बैंक क्रेडिट लिंकेज में बी ग्रेड, नियोजन विभाग को फैमिली आईडी में डी ग्रेड मिला है।

महाकुंभ: ५५ हजार फीट में ११ टन प्राकृतिक रंगों से कलाकारों ने ३ दिन में बनाया

विश्व की सबसे बड़ी रंगोली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा

सांस्कृतिक कार्यक्रम में बही भक्ति की बयार

प्रयागराज। महाकुंभ देश की संस्कृति, अध्यात्म और स्वच्छता का संदेश देता है। इसे रंगों में उतारने का महा प्रयास है। प्रयागराज में तैयार की गई 55 हजार फीट लंबी रंगोली। यह रंगोली न केवल देश की संस्कृति, अध्यात्म और स्वच्छता का संदेश देगी, बल्कि यह विश्व की सबसे बड़ी रंगोली भी होगी। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ और भक्ति की रसधार बही। निगम द्वारा जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में करीब 3 दिनों की मेहनत के बाद यह रंगोली 11 टन प्राकृतिक रंगों और फूलों से तैयार की गई है। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। प्रयागराज और इंदौर की कलाकारों के साझा सहयोग से इसे बनाया गया है। इसमें महाकुंभ की संस्कृति, अध्यात्म और स्वच्छता का संदेश दिखाई दे रहा है। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी कराया जायेगा। शाम को प्रसिद्ध भजन गायक सूर्य प्रकाश दुबे और उनके साथी कलाकारों ने भक्ति रस से हर किसी को सराबोर किया। राधे राध े और श्याम भजन से पूरा माहौल भक्ति भाव में डूब गया। रंगोली प्रयागराज महाकुंभ की संस्कृति, अध्यात्म और स्वच्छता का संदेश देती है। हमें उम्मीद है कि यह रंगोली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगी और प्रयागराज महाकुंभ को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बनाएगी।

महाप्रबन्धक ने जोशी ने संरक्षा पुरस्कार प्रदान किया।

प्रयागराज। नवम्बर माह के लिए महाप्रबन्धकउत्तर मध्य रेलवे उपेन्द्र चन्द्र जोशी प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी जे.सी.एस. बोरा एवं उत्तर मध्य रेलवे के विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में संरक्षा के प्रति किए गए उत्कृष्ट

कार्यों के लिए झांसी, आगरा एवं प्रयागराज मण्डलों से चयनित 10 रेल कर्मचारियों को महाप्रबन्धक महोदय के द्वारा संरक्षा पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कृत कर्मचारियों में 1.श्री मुकेश कुमार लोको पायलट, डीडीयूध्प्रयागराज मण्डल, 2.श्री विक्की कुमार शाहू, सहायक लोको पायलट, डीडीयूध्प्रयागराज मण्डल, 3. श्री रईश पाल सिंह, ट्रेन मैनेजर, पनकी धामध्प्रयागराज मण्डल, 4. श्री राजेश कुमार मीना, कांटेवालाध्रायरूध झांसी मण्डल, 5. श्री जसवन्त कुमार, अवर अभियन्ताध्कै0 एण्ड वै0ध्प्रयागराजध्प्रयागराज मण्डल, 6. श्री राहुल यादव, ट्रेक मेन्टेनर, पन्हाईध्प्रयागराज मण्डल, 7. श्री जयपाल ,ट्रेक मेन्टेनरध फिरोजाबादध प्रयागराज मण्डल, 8. श्री हरिचन्द, ट्रेकमैन, कोसी कलांध्आगरा मण्डल, 9. श्री चांद मोहम्मद, ट्रेकमैन, आगराध आगरा मण्डल, 10. श्री अनिल परिहार, कान्सटेबलध्ग्वालियरध्झांसी मण्डल कर्मचारियों को 2000ध– नकद व प्रशस्ति पत्र तथा विशेष संरक्षा पुरस्कार के रूप में श्री अनिल परिहार, कान्सटेबलध ग्वालियरध झांसी मण्डल को माह का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के लिए 3000ध– एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। अनिल परिहार, कान्सटेबलध ग्वालियरध झाँसी मण्डल ने दिनांक 29.09.24 को 16रू00 से 24रू00 बजे की ड्यूटी के दौरान ग्वालियर स्टेशन पर आगरा छोर की तरफ 21रू41 बजे प्लेटफार्म 01 पर गाड़ी सं0 22182 (गोडवाना एक्सप्रेस) आयी। यह गाड़ी 21रू43 बजे गन्तव्य के लिए रवाना हुई। गाड़ी रवाना होते ही एक महिला यात्री, गाड़ी के जनरल कोच से उतरने का प्रयास करते समय गिर गयी और गाड़ी व प्लेटफार्म के बीच जाने लगी। यह देखकर इन्होंने तत्परता से उक्त महिला यात्री को पकड़कर प्लेटफार्म की तरफ खीच कर उसकी जान बचायी। इनकी सतर्कता एवं सजगता से एक महिला यात्री को बचाया जा सका इस प्रकार इनकी सजगता से कार्य करने के कारण एक संभावित दुर्घटना को बचाया जा सका।

शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना से सम्बंधित आदेश के अनुपालन में पक्षपात का आरोप

प्रयागराज। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पक्षपात कर मनचाहे लोंगो को लाभ दिलाने तथा योजना का अनुपालन पारदर्शी तरीके से नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए समाजवादी शिक्षक सभा के पदाधिकारियों ने आज सपा एमएलसी डॉ मानसिंह यादव एवं सपा शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ एस पी सिंह पटेल केसंयुक्त नेतृत्व में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेन्द्र नाथ तिवारी से उनके कार्यालय में मिलकर शिकायत दर्ज की और ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने के लिये जारी शासनादेश संख्या –14ध2024ध्सा –3–243ध्दस –2024ध301(1)ध2024दिनांक 28जून 2024में निर्देशित है कि जिन भर्तियों का विज्ञापन वर्ष 2005से पहले का है लेकिन कार्यभार समय से नहीं ग्रहण कर पाएं हैं ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाये। ऐसे कर्मचारियों के सत्यापन के नाम पर शिक्षकों से मोटी रकम वसूली जा रही है। विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की मनमानी पर रोक लगाने एवं सभी लाभार्थी कर्मचारियों का सत्यापन पारदर्शी तरीके से किये जाने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से एमएलसी डॉ मानसिंह यादव,शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ एस पी सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष सुरेश यादव, राजू पासी, रंजीत सिंह अवनीश कुमारआदि रहे।

इलाहाबाद स्पोर्टिंग क्लब प्रयागराज पर विशेष कवर जारी

प्रयागराज। प्रधान डाकघर प्रयागराज मे डाक विभाग प्रयागराज एवं इलाहाबाद स्पोर्टिंग क्लब प्रयागराज के सहयोग से इलाहाबाद स्पोर्टिंग क्लब के 125 वर्ष पूरे होने पर एक स्पेशल कवर एवं विरूपण जारी किया गया। जिसके मुख्य अत्तिथि मासूम रजा राशिदी, सहायक निदेशक कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल प्रयागराज एवं अतिथि श्री राजेश कुमार तिवारी, डिप्टी एस.एस.पी. डाकघर प्रयागराज साथ मे श्री रामेंदु राय, अध यक्ष ए.एस.सी. प्रयागराज एवं बिप्लब घोष, सचिव, ए.एस.सी. प्रयागराज रहे। इस विशेष कवर जारी करने पर क्लब के अध्यक्ष रामेंदु राय ने बताया की क्लब की स्थापना वर्ष 1898 को किया गया था क्लब ने फुटबॉल के खेल को संरक्षण एवं बढ़ावा दिया है क्लब ने भारत वर्ष के सभी मुख्य प्रतियोगिता मे भाग लिया क्लब नियमित रूप से फुटबॉल के अतिरिक्त ब्रिज एवं टी.टी. टुनामेंट का आयोजन करती है क्लब फुटबॉल एकेडमी भी चलती है, क्लब ने कई अंतरराष्ट्रिय खिलाडी एवं राष्ट्रिय खिलाडी निकले है , इस विशेष कवर के विमोचन के अवसर पर क्लब के कोषाध्यक्ष संजीव चंद्रा, अमित रौतेला, प्रयाग फिलेटेलिक सोसायटी के अध्यक्ष प्रमोद बंसल, सचिव राहुल गांगुली, एम. गुलरेज, डा. आदित्य सिंह, मुनिस, मो.शारिक, उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन राजेश वर्मा, जन सम्पर्क निरीक्षक, डाक विभाग प्रयागराज के द्वारा किया गया।

भूमि प्रबंधन तकनीक एवं बंजर भूमि सुधार: तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रयागराज। भा.वा.अ.शि.प. पारिस्थितिक पुनर्स्थापन केन्द्र, प्रयागराज द्वारा सतत भूमि प्रबंधन उत्कृष्ठता केन्द्र, देहरादून से प्रायोजित ष्सतत भूमि प्रबंधन तकनीक एवं भूमि क्षरण तटस्थता हेतु दृष्टिकोणष विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 10–12 दिसम्बर, 2024 का शुभारम्भ मुख्य अतिथि तुलसीदास शर्मा, वन संरक्षक, प्रयागराज के दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। केन्द्र प्रमुख डॉ. संजय सिंह ने उपस्थित प्रतिभागियों तथा अतिथियों का स्वागत किया। डॉ. सिंह ने बताया कि भारत के विभिन्न पाँच राज्यों यथा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा कृषि विज्ञान केन्द्र, भूमि संरक्षण राज्य वन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि प्रतिभागियों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान के साथ प्रयागराज के गंगा टास्क फोर्स आदि के लगभग 30 से अधिक प्रतिभागी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। डॉ. सिंह ने कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमि क्षरण के सतत प्रबंधन हेतु विभिन्न तकनीको पर प्रकाश डाला तथा सतत भूमि प्रबंधन उत्कृ ष्ठता केन्द्र, देहरादून की भूमिका की सराहना किया। उन्होंने बताया कि भूमि क्षरण की रोकथाम हेतु जागरूकता अति आवश्यक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तुलसीदास शर्मा, वन संरक्षक, प्रयागराज ने केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए भूमि क्षरण की रोकथाम हेतु एक योजना के अंतर्गत उचित वृक्ष प्रजातियों के चयन द्वारा वृक्षारोपण के माध्यम से वानिकी को बढ़ावा देने पर बल दिया। कार्यक्रम समन्वयक, आलोक यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप रेखा से अवगत कराया। डॉ. हंसराज शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीओई–एसएलएम, देहरादून ने भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के अंतर्गत भूमि प्रबंधन तकनीक एवं भूमि क्षरण सुध ार में केन्द्र की भूमिका से अवगत कराया। केन्द्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा आयोजन सचिव, डॉ. अनुभा श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम तकनिकी सत्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. हंसराज शर्मा द्वारा सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में भूमि क्षरण तटस्थता विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. (डॉ.) उमेश कुमार सिंह ने मरुस्थलीकरण के निदान के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन के अंतर्गत भूमि क्षरण चुनौतियों का समाध ान पर विषय पर चर्चा किया। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के डॉ. पी. सी. अभिलाष, एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा वैश्विक स्थिरता हेतु बंजर भूमि सुधार के अंतर्गत चुनौतियाँ एवं अवसर पर चर्चा किया गया। कार्यक्रम में केन्द्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनीता तोमर, डॉ. कुमुद दूबे, वरिष्ठ तकनीकी अधि ाकारी डॉ. सत्येन्द्र देव शुक्ला, रतन गुप्ता, धर्मेन्द्र कुमार, हरीश कुमार, अम्बूज कुमार उपस्थित रहे।

कोर महाप्रबन्धक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

प्रयागराज। 1988 बैच के आईआरएसई (IRSE) अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को पूर्वाह्न महाप्रबंधक केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर) का पदभार ग्रहण कर लिया। संजय कुमार श्रीवास्तव महाप्रबंधक कोर का पदभार ग्रहण करने के पूर्व त्कै लखनऊ में प्रधान कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा–1)ध ईडी (ट्रैक) के पद पर अक्टूबर 2021 से कार्य कर रहे थे। वह भारतीय रेल में कई अहम पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। अप्रैल 2019 से अगस्त 2021 तक मंडल रेल प्रबंधक, बीकानेर के पद पर तथा अप्रैल 2015 से अप्रैल 2019 तक कार्यकारी निदेशक (गतिशीलता), रेलवे बोर्ड के पद पर भी कार्यरत थे।

आनंद शर्मा वॉलीबाल में राष्ट्रीय निर्णायक बने

प्रयागराज। प्रधान डाकघर प्रयागराज मे कार्यरत कर्मचारी आनंद शर्मा को 68 वी राष्ट्रीय विधालयी वॉलीबाल चौंपियनशिप जो वराणासी मे दिनाक 10 दिसंम्बर से 14 दिसंम्बर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। जिसमे आनंद शर्मा को उत्तर प्रदेश वॉलीबाल एसोसिएशन द्वारा निर्णायक बनाया गया। आनंद शर्मा वॉलीबाल के राष्ट्रीय खिलाडी भी है। डाक विभाग में स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत भर्ती हुए है। आनंद को राष्ट्रीय निर्णायक बनाये जाने पर राजेश वर्मा, प्रमोद राय, गौरव कुमार, खुर्शीद अकरम, डी वी ए के अध्यक्ष प्रभात राय, विमल पाण्डे, हरि शंकर, रवि यादव , आशीष दिरवेदी, अरविंद यादव, मो.अशद ने बधाई दिया उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया।

नगर आयुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी का वेतन रोका।

प्रयागराज। नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग ने निवृत्त, मृतक कर्मचारियों के देय भुगतान की कार्यवाही हेतु आदेश दिये जाते रहे है। परन्तु दिये गये निर्देशों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग नगर निगम द्वारा 25 सेवा निवृत्तध मृतक कर्मचारियों के लम्बित प्रकरणों को रखा गया जिसके कारण नगर निगम के विरूद्ध दायर हो रही याचिकाओं का न केवल सामना करना पड़ रहा है बल्कि आपके इस कृत्य से नगर निगम की छवि भी प्रभावित हो रही है तथा कर्मचारी भी अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नगर आयुक्त चन्द्र मोहन गर्ग द्वारा नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा0 महेश कुमार को 03 दिवस का स्पष्टीकरण जारी किया किया गया है, साथ ही संतोषजन उत्तर प्राप्त होने के पष्चात ही माह दिसम्बर 2024 का वेतन आहरित करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी प्रयागराज को संस्तुति की गयी।

नाजरेथ अस्पताल ने 49वें स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक भव्यता के साथ मनाया

नाजरेथ अस्पताल के मंच पर गूंजा 'महाकुंभ'

प्रयागराज। नाजरेथ अस्पताल ने अपने 49वें स्थापना दिवस को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ उत्साहपूर्वक मनाया। इस विशेष अवसर पर सोनभद्र जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाजरेथ अस्पताल के चेयरमैन, माननीय मोस्ट रेवरेण्ड लुईस मास्करेन्हस ने की। विषिश्ट अतिथियों में प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. आशु पांडे और कांग्रेगेशन ऑफ सिस्टर्स ऑफ नाजरेथ की प्रांतीय सुपीरियर सिस्टर लता सीएसएन शामिल थीं। समारोह की शुरुआत एक भावपूर्ण प्रार्थना नृत्य के साथ हुई, जिसने कार्यक्रम को आध्यात्मिक रंग दिया। इसके बाद 'दीप प्रज्वलन' का समारोह आयोजित किया गया, जो आशा और ज्ञान का प्रतीक था। प्रशासक माननीय फादर इसिडोर डीसूजा ने गणमान्य अतिथियों, मेहमानों और शुभचिंतकों का स्वागत करते हुए सांस्कृतिक भव्यता की शुरुआत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं। इनमें से सबसे प्रमुख थी 'महाकुंभ दी इटार्नल कान्फ्लुएंस', जो महाकुंभ मेले के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का भव्य चित्रण था। इस प्रदर्शन ने महाकुंभ की गहरी परंपराओं और एकता तथा भक्ति के सार्वभौमिक संदेश को प्रस्तुत किया। दर्शकों ने इसे जोरदार तालियों से सराहा, जो प्रयागराज की समृद्ध विरासत की गूंज थी।

सम्पादक
सिद्धनाथ द्विवेदी
प्रबन्धक निदेशक
दीपक जयसवाल
सम्पादकीय कार्यालय
11ई/2, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के आधीन होगा।

महाकुम्भ 2025 के दौरान रेलगाड़ियों का अस्थाई ठहराव

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित श्रद्धालुओं/रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ मेला-2025 के दौरान विशेष रेलगाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(1) गाड़ी सं. 08251/08252 (रायगढ़-वाराणसी-रायगढ़) विशेष रेलगाड़ी

08251 रायगढ़-वाराणसी		स्टेशन	08252 वाराणसी-रायगढ़	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
--	14:00	रायगढ़	05:25	--
03:00	03:02	मानिकपुर	17:00	17:02
05:10	05:20	प्रयागराज छिवकी	14:15	14:25
06:23	06:25	मिर्जापुर	12:18	12:20
07:10	07:12	चुनार	11:50	11:52
10:00	--	वाराणसी	--	10:50

गाड़ी सं. 08251 रायगढ़ जं. से शनिवार, दिनांक 25.01.2025 को एवं गाड़ी सं. 08252 वाराणसी से सोमवार, दिनांक 27.01.2025 को चलेगी।

अन्य ठहराव: उपरोक्त स्टेशनों के अतिरिक्त यह गाड़ी चाँपा जं., बिलासपुर, पेन्ड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर तथा सतना पर भी रुकेगी।

संरचना: सामान्य श्रेणी-04, स्लीपर श्रेणी-14, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी-01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-01

(2) गाड़ी सं. 08791/08792 (दुर्ग-वाराणसी-दुर्ग) विशेष रेलगाड़ी

08791 दुर्ग-वाराणसी		स्टेशन	08792 वाराणसी-दुर्ग	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
--	13:50	दुर्ग	05:30	--
03:00	03:02	मानिकपुर	17:00	17:02
05:10	05:20	प्रयागराज छिवकी	14:15	14:25
06:23	06:25	मिर्जापुर	12:18	12:20
07:10	07:12	चुनार	11:50	11:52
10:00	--	वाराणसी	--	10:50

गाड़ी सं. 08791 दुर्ग से शनिवार, दिनांक 08.02.2025 को एवं गाड़ी सं. 08792 वाराणसी से सोमवार, दिनांक 10.02.2025 को चलेगी।

अन्य ठहराव: उपरोक्त स्टेशनों के अतिरिक्त यह गाड़ी रायपुर, भाटापारा, उसलापुर, पेन्ड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर और सतना पर भी रुकेगी।

संरचना: सामान्य श्रेणी-04, स्लीपर श्रेणी-14, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी-01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-01

(3) गाड़ी सं. 08253/08254 (बिलासपुर-वाराणसी-बिलासपुर) विशेष रेलगाड़ी

08253 बिलासपुर-वाराणसी		स्टेशन	08254 वाराणसी-बिलासपुर	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
--	08:15	बिलासपुर	--	10:40
03:00	03:02	मानिकपुर	17:00	17:02
05:10	05:20	प्रयागराज छिवकी	14:15	14:25
06:23	06:25	मिर्जापुर	12:18	12:20
07:10	07:12	चुनार	11:50	11:52
10:00	--	वाराणसी	--	10:50

गाड़ी सं. 08253 बिलासपुर से शनिवार, दिनांक 22.02.2025 को एवं गाड़ी सं. 08254 वाराणसी से सोमवार, दिनांक 24.02.2025 को चलेगी।

अन्य ठहराव: उपरोक्त स्टेशनों के अतिरिक्त यह गाड़ी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर एवं सतना पर भी रुकेगी।

संरचना: सामान्य श्रेणी-04, स्लीपर श्रेणी-14, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी-01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-01

नोट : यदि नई समय सारणी दिनांक 01.01.2025 से लागू होती है, तो स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव के लिए दिए गए समय में परिवर्तन हो सकता है।

ट्रेनों की समय-सारणी से सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नं0 139 या Rail Madad Mobile App. या वेबसाइट www.railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

1800 4199 139 उत्तर मध्य रेलवे

@CPRONCR North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in 2104/24 FA

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक सिद्धनाथ द्विवेदी द्वारा काम्पीटेंट बिजनेस सर्विसेज विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित एवं 399 कृष्णानगर कीडगंज से प्रकाशित।
सम्पादक–सिद्धनाथ द्विवेदी, आरएनआई नं. UPHIN/2007/22706 रजि.नं. AD-32/2008-09 ईमेल: amritkt.alld@gmail.com फोन नं. : 9453273951, 8799627062